

मंथली पॉलिसी रिव्यू

अक्टूबर 2024

इस अंक की झलकियां

2024-25 की दूसरी तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 4.2%

सीपीआई मुद्रास्फीति पिछले वर्ष की समान तिमाही (6.4%) से कम थी। 2024-25 की दूसरी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 6.8% रही और अगस्त (5.7%) की तुलना में सितंबर महीने (9.2%) में इसमें काफी वृद्धि हुई।

सर्वोच्च न्यायालय ने बांग्लादेश से असम आए प्रवासियों के लिए नागरिकता संबंधी कानून को बरकरार रखा

न्यायालय ने माना कि असम के लिए एक अलग प्रावधान उचित वर्गीकरण पर आधारित था। यह भी माना गया कि कानून में कट-ऑफ तारीखें ऐतिहासिक परिस्थितियों पर आधारित हैं, और इस प्रकार यह मनमाना प्रावधान नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने औद्योगिक अल्कोलहल को रेगुलेट करने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नशीली शराब में पीने योग्य शराब के अलावा अन्य शराब भी शामिल हो सकती है। यह भी माना कि संसद नशीली शराब के उद्योग को नियंत्रित करने के लिए कानून नहीं बना सकती।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने पीएम इंटरनशिप योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए

पायलट प्रोजेक्ट के दिशानिर्देशों में कंपनियों के लिए मानदंड, इंटरनशिप की अवधि, इंटरनशिप के लिए पात्रता, इंटरन को लाभ और कंपनियों द्वारा सीएसआर फंड के उपयोग को निर्दिष्ट किया गया है।

खेल मंत्रालय ने खेल प्रशासन पर ड्राफ्ट बिल जारी किया

ड्राफ्ट बिल भारत में एक रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना करता है। यह बोर्ड राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और विभिन्न खेलों के राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता प्रदान करेगा।

कैबिनेट ने मौजूदा कृषि योजनाओं को सुसंगठित करने को मंजूरी दी

कैबिनेट ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को दो व्यापक योजनाओं में सुसंगठित करने को मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी

सभी कल्याणकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की मुफ्त आपूर्ति दिसंबर 2028 तक जारी रहेगी।

कैबिनेट ने अंतरिक्ष आधारित स्टार्टअप्स के लिए 1,000 करोड़ रुपये की फंडिंग को मंजूरी दी

इस धनराशि का उपयोग पांच वर्षों में किया जाएगा। इसकी प्रारंभिक अवधि 2025-26 है। इसका लक्ष्य करीब 40 अंतरिक्ष-आधारित स्टार्टअप्स को लाभ पहुंचाना है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) 2022-32 के लिए अधिसूचित

राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, 2022-32 में 1.91 लाख सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने की योजना है।

मैक्रोइकोनॉमिक विकास

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

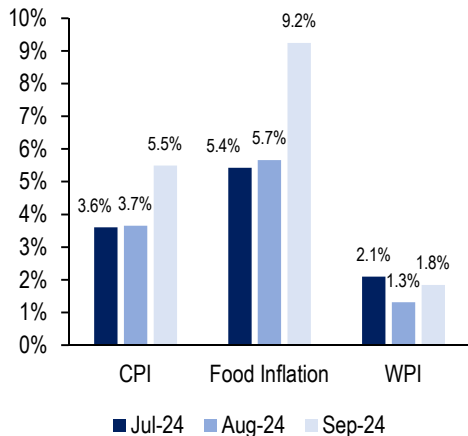
2024-25 की दूसरी तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 4.2%

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 2024-25 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 4.2% रही जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 6.4% की दर से कम है।¹ 2024-25 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में सीपीआई मुद्रास्फीति 4.9% थी।

2024-25 की दूसरी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 6.8% रही। यह 2023-24 की इसी तिमाही में 9.4% की खाद्य मुद्रास्फीति की तुलना में कम थी। 2024-25 की पहली तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति 8.9% थी।

2024-25 की दूसरी तिमाही में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति 1.8% थी जो पिछले वर्ष की समान तिमाही (-0.6%) से अधिक है।² 2024-25 की पहली तिमाही में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति औसतन 2.5% थी।

रेखाचित्र 1: 2024-25 की पहली तिमाही में मासिक मुद्रास्फीति (% परिवर्तन, वर्ष-दर-वर्ष)



स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; पीआरएस।

रेपो रेट 6.5% पर अपरिवर्तित

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने पॉलिसी रेपो रेट (जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है) को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है।³ समिति के अन्य निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टैंडिंग डिपॉजिट फेसिलिटी रेट (जिस दर पर आरबीआई कोलेट्रल दिए बिना बैंकों से उधार लेता है) को 6.25% पर बरकरार रखा गया है।
- मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी रेट (जिस दर पर बैंक अतिरिक्त धन उधार ले सकते हैं) और बैंक रेट (जिस दर पर आरबीआई बिल्स ऑफ़ एकसचेंज को खरीदता है) को 6.75% पर बरकरार रखा गया है।

एमपीसी ने समायोजन की वापसी पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। इससे यह सुनिश्चित होने की उम्मीद है कि विकास को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर 4% के लक्ष्य के अनुरूप हो।

कॉर्पोरेट मामले

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

प्रधानमंत्री इंटरनेशिप योजना के पायलट के लिए दिशानिर्देश जारी

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटरनेशिप योजना- पायलट प्रोजेक्ट के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।⁴ इस योजना की घोषणा 2024-25 के बजट में की गई थी और इसका लक्ष्य पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को इंटरनेशिप देना है। 1.25 लाख इंटरनेशिप देने के लक्ष्य के साथ 2024-25 के लिए योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कंपनियों के मापदंड:** इंटरनेशिप की पेशकश के लिए पिछले तीन वर्षों में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) पर उनके औसत व्यय के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों का चयन किया गया है। अन्य कंपनियां मंत्रालय से मंजूरी लेकर इस योजना में भाग ले सकती हैं।
- अवधि:** इंटरनेशिप की अवधि 12 महीने होनी चाहिए। इसका कम से कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य अनुभव/कार्य के माहौल पर खर्च किया जाना चाहिए।
- इंटरनेशिप के लिए पात्रता:** 21 से 24 वर्ष की आयु के उम्मीदवार इंटरनेशिप पाने के पात्र होंगे। वे पूर्णकालिक रोजगार या पूर्णकालिक शिक्षा में संलग्न नहीं होने चाहिए। हालांकि ऑनलाइन/दूरस्थ

शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। निम्नलिखित व्यक्ति योजना के लिए पात्र नहीं हैं: (i) आईआईटी, आईआईएम और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जैसे संस्थानों से ग्रेजुएट्स, (ii) प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस या मास्टर डिग्री वाले व्यक्ति, और (iii) 2023-24 में 8 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों से संबंधित लोग।

- **इंटर्न्स को लाभ:** इंटर्न्स को 5,000 रुपए की मासिक सहायता का भुगतान किया जाएगा। कंपनी अपने सीएसआर फंड से इंटर्न्स को हर महीने 500 रुपए देगी। इसके बाद केंद्र सरकार उम्मीदवार को शेष 4,500 रुपए का भुगतान करेगी। इंटर्न्शिप लोकेशन में ज्वाइन करने पर इंटर्न्स को केंद्र सरकार से 6,000 रुपए का एकमुश्त अनुदान भी मिलेगा।
- **सीएसआर फंड्स का उपयोग:** कंपनियां अपने सीएसआर फंड से इंटर्न्स के प्रशिक्षण पर खर्च करेंगी। इसके अलावा योजना के तहत किए गए सीएसआर व्यय का 5% तक कंपनी द्वारा प्रशासनिक लागत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

कानून एवं न्याय

Rutvik Upadhyaya (rutvik@prsindia.org)

सर्वोच्च न्यायालय ने बांग्लादेश से असम आने वाले प्रवासियों के लिए नागरिकता के प्रावधान बरकरार रखे

4:1 के बहुमत के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता एक्ट, 1955 के उस प्रावधान को बरकरार रखा, जो बांग्लादेश से असम में आने वाले प्रवासियों के लिए एक अलग नागरिकता मानदंड प्रदान करता है।^{5,6} इस प्रावधान के अनुसार, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति: (i) जिसने 1 जनवरी, 1966 से पहले बांग्लादेश से असम में प्रवेश किया था, और (ii) तब से आमतौर पर असम में रह रहा है, वह एक भारतीय नागरिक है। हालांकि 1 जनवरी, 1966 के बाद और 25 मार्च, 1971 से पहले प्रवास करने वाले व्यक्ति को विदेशी के रूप में पहचाने जाने की तारीख से 10 वर्ष पूरा होने पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। पंजीकरण होने पर उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा लेकिन

उसका नाम मतदाता सूची से 10 वर्ष के लिए हटा दिया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने जिन मुख्य सवालों की जांच की, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) संसद के पास इस तरह का कानून पारित करने की क्षमता है, (ii) असम के लिए अलग प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, और (iii) प्रावधान के तहत कट-ऑफ तारीखें मनमानी हैं।

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद के पास नागरिकता पर कोई भी कानून पारित करने की क्षमता है। यह क्षमता प्रश्नगत प्रावधान को कानून बनाने तक विस्तारित है। न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि एक्ट के तहत असम के लिए एक अलग प्रावधान समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन नहीं करता है।⁷ प्रवासियों की आमद से असम में बनी अनोखी राजनीतिक स्थिति के आधार पर असम और शेष भारत को अलग किया जाता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस प्रावधान के तहत कट-ऑफ तारीखें मनमानी नहीं हैं क्योंकि वे विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं और परिस्थितियों पर आधारित हैं।

व्यापार एवं वाणिज्य

Shrusti Singh (shrusti@prsindia.org)

सर्वोच्च न्यायालय ने औद्योगिक अल्कोहल को रेगुलेट करने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा

सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सात न्यायाधीशों की एक पिछली पीठ के फैसले को पलट दिया और डीनेचर्ड स्पिरिट या औद्योगिक अल्कोहल को रेगुलेट करने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा।⁸ संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के तहत, राज्यों को नशीली शराब के उत्पादन, निर्माण, कब्जे, परिवहन, खरीद और बिक्री को रेगुलेट करने का अधिकार है।⁹

न्यायालय विभिन्न प्रकार की शराब के रेगुलेशन और टैक्सेशन के संबंध में संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की समीक्षा कर रहा था। न्यायालय ने जांच की कि क्या सार्वजनिक हित में उद्योगों पर संघ का नियंत्रण (सूची I की प्रविष्टि 52) राज्यों के नशीली शराब को रेगुलेट करने के अधिकार (सूची II की

प्रविष्टि 8) से अधिक है। न्यायालय ने माना कि संविधान राज्यों को कच्चे माल के स्तर से लेकर उपभोग तक नशीली शराब को रेगुलेट करने का अधिकार देता है। उसने कहा कि संसद नशीली शराब के उद्योग को रेगुलेट करने के लिए कानून नहीं बना सकती। ऐसा करने से राज्य ऐसे उद्योग को रेगुलेट करने की अपनी विशेष विधायी क्षमता खो देंगे।

न्यायालय ने एक अन्य प्रश्न की जांच की कि क्या नशीली शराब में पीने योग्य शराब के अलावा अन्य शराब भी शामिल है। यह माना गया कि सूची II की प्रविष्टि 8 के तहत नशीली शराब में सभी अल्कोहल शामिल हैं जिनका उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य की क्षति के लिए हानिकारक रूप से किया जा सकता है। इसमें पीने योग्य अल्कोहल और अन्य उत्पादों के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली रेक्टिफाइड स्पिरिट और औद्योगिक स्पिरिट (मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त) शामिल हैं।

कृषि

Shrusti Singh (shrusti@prsindia.org)

कैबिनेट ने सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए योजनाओं के सुसंगठन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत सभी मौजूदा केंद्र प्रायोजित योजनाओं को दो प्रमुख योजनाओं में सुसंगठित करने को मंजूरी दी: (i) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई), और (ii) कृष्णोन्नति योजना।¹⁰

सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए 57,075 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम-आरकेवीवाई को लागू किया जाएगा। पीएम-आरकेवीवाई के तहत कुछ योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, (ii) वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, (iii) कृषि वानिकी, और (iv) कृषि मशीनीकरण। राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक घटक से दूसरे घटक में धनराशि को पुनः आवंटित करने की सुविधा होगी।

कृष्णोन्नति योजना का लक्ष्य 44,247 करोड़ रुपए के प्रस्तावित परिव्यय के साथ आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना होगा।

कैबिनेट ने तिलहन उत्पादन मिशन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन (एनएमईओ-तिलहन) को मंजूरी दे दी।¹¹ मिशन को 2024-25 से 2030-31 के बीच 10,103 करोड़ रुपए के प्रस्तावित आवंटन के साथ लागू किया जाएगा। मिशन का लक्ष्य प्राथमिक तिलहन फसलों का उत्पादन 2022-23 में 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030-31 तक 70 मिलियन टन करना है। इनमें रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल शामिल हैं। 2023-24 में घरेलू खाद्य तेल उत्पादन 12 मिलियन टन होने का अनुमान है।¹² एनएमईओ-ऑयल पाम के साथ इस मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को 25 मिलियन टन तक बढ़ाना है। घरेलू उत्पादन में इस अनुमानित वृद्धि से 2030-31 तक भारत की अनुमानित आवश्यकता का 72% पूरा होने की उम्मीद है। बीज उत्पादन के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 65 नए बीज केंद्र और 50 बीज भंडारण इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 में सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है (तालिका 1 देखें)।¹³ एमएसपी उस सुनिश्चित मूल्य को कहा जाता है जिस पर केंद्र सरकार किसानों से फसल खरीदती है।¹⁴ गेहूं के लिए एमएसपी में 6.6% की बढ़ोतरी हुई है। एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जौ के लिए (7%) घोषित की गई है।

तालिका 1: मार्केटिंग सीजन 2025-26 में रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

फसल	एमएसपी 2024-25	एमएसपी 2025-26	% परिवर्तन
गेहूं	2,275	2,425	6.6%
जौ	1,850	1,980	7.0%
चना	5,440	5,650	3.9%
मसूर दाल	6,425	6,700	4.3%
रेपसीड और सरसों	5,650	5,950	5.3%
कुसुम	5,800	5,940	2.4%

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो; पीआरएस।

कैबिनेट ने पीएमजीकेवाई के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सहित सभी कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी है।¹⁵ मुफ्त आपूर्ति को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। चावल फोर्टिफिकेशन में नियमित चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले चावल के दाने मिलाए जाते हैं। इसे केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया जाएगा।

युवा मामले एवं खेल

Rutvik Upadhyaya (rutvik@prsindia.org)

खेल मंत्रालय ने खेल प्रशासन पर ड्राफ्ट बिल जारी किया

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन बिल, 2024 का ड्राफ्ट जारी किया है।¹⁶ यह बिल निम्नलिखित की मान्यता और रेगुलेशन के लिए एक रेगुलेटरी संरचना बनाता है: (i) राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (एनओसी), (ii) राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (एनपीसी) और (iii) राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ)। बिल के ड्राफ्ट की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **रेगुलेटर:** बिल के ड्राफ्ट में भारतीय खेल रेगुलेटरी बोर्ड के निर्माण का प्रावधान है। बोर्ड विभिन्न खेलों के एनओसी, एनपीसी और एनएसएफ को रेगुलेट करेगा। उसे इन निकायों को मान्यता देने, उनका नवीनीकरण करने या उन्हें निलंबित करने का अधिकार होगा। बोर्ड एथलीट्स और सपोर्ट स्टाफ के अधिकारों की रक्षा करेगा और उनका कल्याण सुनिश्चित करेगा।
- **निलंबन:** एनओसी, एनपीसी और एनएसएफ की मान्यता निम्नलिखित से उनकी संबद्धता पर सशर्त है: (i) अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक या पैरालंपिक समिति (एनओसी और एनपीसी के लिए) या, (ii) संबंधित अंतरराष्ट्रीय महासंघ (एनएसएफ के लिए)। संबद्धता बनाए रखने में विफलता के कारण निलंबन हो सकता है। निलंबन के अन्य

कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) आंतरिक कामकाज में अनियमितताएं, (ii) एकाउंट्स को पब्लिश न करना, और (iii) चुनाव प्रक्रियाओं में अनियमितताएं। अगर निलंबन का कारण सुधार योग्य है, तो बोर्ड इसके बजाय अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।

- **गवर्नेंस:** ड्राफ्ट बिल एनओसी, एनपीसी और हरेक एनएसएफ के गवर्नेंस की संरचना में कुछ विशिष्टताएं प्रदान करता है। इन निकायों में से प्रत्येक में एक सामान्य निकाय (जनरल बॉडी) और कार्यकारी समिति (एग्जीक्यूटिव कमिटी) होनी चाहिए। कार्यकारी समिति, जो एक गवर्निंग बॉडी है, का चुनाव एथलीट आयोग द्वारा किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव जैसे पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें एथलीट भी शामिल होंगे। लगातार दो से अधिक कार्यकाल तक सेवा करने के बाद, पदाधिकारी कम से कम चार वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे।
- प्रत्येक निकाय में सामान्य निकाय और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम 10% उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी (एसओएम) होंगे। एसओएम ऐसे सेवानिवृत्त एथलीट्स को कहा जाता है जिन्होंने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल या एशियाई खेलों में कम से कम एक पदक जीता है।
- **ट्रिब्यूनल:** ड्राफ्ट बिल एक अपीलीय खेल ट्रिब्यूनल की स्थापना करता है। केंद्र सरकार सदस्यों की संरचना, चयन के तरीके और उन मामलों को अधिसूचित करेगी जिन पर ट्रिब्यूनल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। ट्रिब्यूनल का चयन सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति के सुझावों पर किया जाएगा।

स्वास्थ्य

Shirin Pajnoo (shirin@prsindia.org)

स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी रोगियों के लिए पोषण सहायता का दायरा बढ़ाया

स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में नि-क्षय पोषण योजना के विस्तार की घोषणा की है।¹⁷ इस योजना का उद्देश्य टीबी के कारण मृत्यु दर को कम करने के लिए टीबी रोगियों को पोषण और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

प्रत्येक टीबी रोगी के लिए वित्तीय सहायता 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह की जाएगी। यह योजना कम वजन वाले टीबी रोगियों को उपचार के पहले दो महीनों के लिए ऊर्जा-सघन पोषण संबंधी खुराक भी प्रदान करेगी। टीबी रोगियों के परिवार के सदस्यों को भी पोषण संबंधी सहायता मिलेगी जिसका उद्देश्य उनकी प्रतिरक्षा (इम्युनिटी) में सुधार करना होगा।

योजना के विस्तार की लागत 1,040 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसे केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में वितरित किया जाएगा।

विज्ञान एवं तकनीक

Anirudh TR (anirudh@prsindia.org)

कैबिनेट ने अंतरिक्ष आधारित स्टार्टअप्स के लिए 1,000 करोड़ रुपए की फंडिंग को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष-आधारित स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष की स्थापना को मंजूरी दी।¹⁸ यह कोष भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन्स्पेस) (INSPACE) द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और निगरानी करने के लिए सरकार द्वारा 2020 में इन्स्पेस बनाया गया था। यह कोष 2025 से 2030 तक पांच वर्ष की अवधि में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें वार्षिक उपयोग 150-200 करोड़ रुपए होगा। स्टार्टअप्स में निवेश की सांकेतिक सीमा 10-60 करोड़ रुपए के बीच है। वृद्धि चरण की कंपनियां 10-30 करोड़ रुपए के बैंड में निवेश कर सकती हैं। लंबित वृद्धि चरण वाली कंपनियां, जिन्होंने महत्वपूर्ण प्रगति

प्रदर्शित की है, 30-60 करोड़ रुपए के बैंड में निवेश कर सकती हैं। इस कोष से अंतरिक्ष आधारित लगभग 40 स्टार्टअप कंपनियों को फायदा होने की उम्मीद है। इस कोष के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) आगे के निवेश के लिए मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करने हेतु पूंजी निवेश, (ii) भारत में अधिवासित अंतरिक्ष कंपनियों को यहीं बरकरार रखना, और (iii) भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी में तेजी लाना।

पर्यावरण

Atri Prasad Rout (atri@prsindia.org)

पर्यावरण मंत्रालय ने तरल अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के ड्राफ्ट पर टिप्पणियां मांगी

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तरल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 के ड्राफ्ट पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं।¹⁹ नियम पर्यावरण (संरक्षण) एक्ट, 1986 के तहत जारी किए गए हैं।²⁰ तरल अपशिष्ट प्रबंधन में पर्यावरण की दृष्टि से निम्नलिखित का उचित प्रबंधन शामिल है: (i) अपशिष्ट जल, (ii) अपशिष्ट जल उपचार के दौरान पैदा होने वाला स्लज और फीकल स्लज, और (iii) उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग। ड्राफ्ट नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- थोक उपयोग की जिम्मेदारियां:** बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) के संदर्भ में प्रति दिन 5,000 लीटर से अधिक पानी की खपत या प्रति दिन 10 किलोग्राम से अधिक प्रदूषण भार वाले प्रतिष्ठानों को एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। बीओडी पानी में प्रदूषकों के स्तर का माप होता है। ये उपयोगकर्ता विस्तारित उपयोगकर्ता जिम्मेदारी (ईयूआर) दायित्व से बंधे होंगे। वे निम्नलिखित करेंगे: (i) ऑनसाइट विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार सुविधाएं संचालित करना, और (ii) उपचारित अपशिष्ट जल के न्यूनतम पुनः उपयोग के दायित्व को पूरा करना। जो उपयोगकर्ता ऑनसाइट सुविधा स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं, वे पंजीकृत अपशिष्ट जल उपचार सुविधाओं से ईयूआर प्रमाणपत्र खरीद

सकते हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन ईयूआर प्रमाणपत्रों को अधिकृत करेगा।

- **उद्योगों की जिम्मेदारियां:** जिन उद्योगों में प्रति दिन 5,000 लीटर से अधिक पानी की खपत होती है या बीओडी की अवधि में प्रति दिन 10 किलोग्राम से अधिक प्रदूषण भार होता है, उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। उन्हें निम्नलिखित करना होगा: (i) केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा निर्धारित अपशिष्ट निर्वहन मानकों का पालन करना, और (ii) औद्योगिक अपशिष्ट के उपचार की सुविधा करना। थर्मल पावर प्लांट, स्टील और कपड़ा जैसे उद्योगों को उपचारित अपशिष्ट जल के न्यूनतम पुनः उपयोग के दायित्व को पूरा करना होगा।
- **फीकल वेस्ट का प्रबंधन:** सैप्टिक टैंक जैसी ऑनसाइट स्वच्छता सुविधाओं के उपयोगकर्ता इन सुविधाओं से डीस्लजिंग के लिए जिम्मेदार होंगे। डीस्लजिंग वाले सेवा प्रदाताओं और फीकल स्लज की उपचार सुविधाओं के संचालकों दोनों को: (i) ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, और (ii) मासिक और वार्षिक आधार पर डेटा रिपोर्ट करना होगा। स्थानीय निकाय फीकल स्लज के पर्यावरणीय रूप से उत्तम प्रबंधन के लिए कार्य योजनाएं विकसित करेंगे।

टिप्पणियां 6 दिसंबर, 2024 तक आमंत्रित हैं।

ऊर्जा

Nripendra Singh (nripendra@prsindia.org)

2022-32 के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) अधिसूचित

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2022-32 के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) (वॉल्यूम- II ट्रांसमिशन) को अधिसूचित किया है।²¹ मई 2023 में सीईए ने एनईपी (वॉल्यूम-I उत्पादन) को अधिसूचित किया था।²² सीईए को बिजली एक्ट, 2003 के तहत पांच वर्ष में एक बार राष्ट्रीय बिजली योजना तैयार करनी होती है।²³ योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- **मौजूदा क्षमता और लक्ष्य:** 31 मार्च, 2022 तक, भारत में कुल 4,56,716 सर्किट किलोमीटर (ckm) की स्थापित ट्रांसमिशन लाइनें थीं। एनईपी की योजना 2022-32 के दौरान 1,91,474 ckm ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने की है (220 kV और उससे ऊपर के वोल्टेज स्तर पर)।
- **2017-22 के लक्ष्य पूरे नहीं हुए:** 2017-22 के दौरान 1,04,400 ckm ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य के मुकाबले, केवल 88,865 ckm (85%) ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी गईं। योजना में कहा गया है कि 2017-2022 के लिए लक्ष्य क्षमता वृद्धि को कोविड-19 महामारी और वन मंजूरी मिलने में देरी जैसे कारणों से हासिल नहीं किया जा सका।
- **अक्षय ऊर्जा लक्ष्य:** योजना में कहा गया है कि 31 मई, 2024 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 193.5 GW थी। उसमें कहा गया कि कुछ अक्षय ऊर्जा-आधारित उत्पादन परियोजनाओं की कालावधि इससे संबंधित ट्रांसमिशन प्रणाली की तुलना में कम है। इसके लिए ट्रांसमिशन सिस्टम की योजना पहले से बनाने की आवश्यकता थी। एनईपी 2032 तक 613 GW की अक्षय ऊर्जा क्षमता से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली स्थापित करने की योजना प्रदान करता है।

पीएम-सूर्य घर योजना के तहत नई परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित

नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम-सूर्य घर योजना के तहत नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।²⁴ इस योजना का लक्ष्य सोलर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय परिवारों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाना है। योजना के तहत नई परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिससे रूफटॉप सोलर टेक्नोलॉजीज में प्रगति को प्रोत्साहित और बिजनेस मॉडल में नए प्रयोगों को वित्त पोषित किया जा सके।²⁵

यह योजना संयुक्त अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग सहित संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए खुली है। योजना के तहत परियोजनाओं की अधिकतम अवधि

18 महीने हो सकती है। चयनित परियोजनाओं को उनकी कुल लागत का 60% या 30 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रस्तावित परियोजनाओं की जांच एक समिति द्वारा निम्नलिखित के आधार पर की जाएगी: (i) प्रासंगिकता और लागत-प्रभावशीलता, (ii) परियोजना अवधारणा और नवीनता, और (iii) समाज के लिए महत्व। स्क्रीनिंग कमिटी के प्रस्तावों का चयन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमिटी द्वारा किया जाएगा।

अनुलग्नक

संसद ने अपनी कुछ विभागीय स्थायी समितियों का गठन किया है। समितियों द्वारा 2024-25 में समीक्षा के लिए चिन्हित विषय निम्नलिखित हैं।

तालिका 2: विभागीय संबंधित स्थायी समितियों द्वारा समीक्षा के लिए चिन्हित विषय

कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

1. देश में प्रमाणित बीजों का उत्पादन एवं उपलब्धता
2. देश में कृषि ऋण प्रणाली की कार्यप्रणाली
3. देश में तिलहन और दालों का उत्पादन और उपलब्धता
4. कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन
5. जैविक और प्राकृतिक खेती- संभावनाएं और चुनौतियां
6. कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन
7. पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग का प्रभाव- उनके उपयोग को सुसंगठित करने के तरीके
8. वैज्ञानिक और तकनीकी तरीकों से फसल अवशेषों के प्रबंधन में किसानों और सरकार की भूमिका
9. स्वामीनाथन समिति रिपोर्ट के सुझावों के कार्यान्वयन की स्थिति
10. किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नीतियां और परियोजनाएं
11. कृषि सबसिडी का प्रभाव रिपोर्ट
12. जल संसाधन (भूजल सहित), सिंचाई प्रणाली, वर्षा सिंचित, वाटरशेड कार्यक्रम और जल निकासी प्रबंधन के लिए नीतियां और परियोजनाएं
13. कृषि उपज के मूल्य निर्धारण के लिए नीति निर्धारण
14. फसलों के विविधीकरण के लिए नीतियां
15. कृषि आदानों का गुणवत्ता नियंत्रण
16. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद- एक समीक्षा

17. फसल बीमा योजना के प्रदर्शन की समीक्षा
18. छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि मशीन उपकरण और अन्य उपकरणों पर जीएसटी को सुसंगठित करना
19. मुख्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना- सरकारी पहल एवं उपाय
20. किसानों की आत्महत्या के मुख्य सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों की पहचान करना
21. छोटे और सीमांत किसानों तक मनरेगा योजनाओं के लाभों का विस्तार
22. कृषि उपज विपणन प्रणाली का विकास एवं संवर्धन
23. देश में फूलों की खेती को बढ़ावा- संभावनाएं और चुनौतियां
24. खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम वेतन का प्रावधान
25. खस-खस की खेती- संभावनाएं और चुनौतियां
26. कटाई के बाद नमी प्रबंधन और भंडारण के दौरान नमी के नुकसान का मानकीकरण
27. प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान के लिए काश्तकारों सहित किसानों को मुआवजा (सिर्फ फसला बीमा योजना ही नहीं)
28. मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) की जांच; और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)
29. छोटे और सीमांत किसानों और एससी/एसटी किसानों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियां और प्रावधान
30. शहरीकरण, औद्योगिकरण और राष्ट्रीय राजमार्गों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए कृषि भूमि के अंधाधुंध अधिग्रहण के कारण घटती उपजाऊ भूमि - एक समीक्षा
31. जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कृषि अनुसंधान में आईसीएआर का योगदान
32. कटाई उपरांत फसल प्रबंधन में अनुसंधान एवं विकास
33. केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर- प्रदर्शन की समीक्षा
34. देश में कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की भूमिका और प्रदर्शन का मूल्यांकन
35. कृषि में प्रदूषण और मिट्टी में नाइट्रोजन अक्षमता से निपटने के लिए अनुसंधान पहल और परियोजनाएं
36. भूजल बचाने के लिए बीजों की जल कुशल किस्म विकसित करने के लिए अनुसंधान
37. सभी सरकारी वित्त पोषित कृषि अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और आईसीएआर की प्रदर्शन समीक्षा
38. जेनेटिकली मॉडिफाइड, इंजीनियर्ड, कृत्रिम और टर्मिनेटर बीजों के उपयोग पर नीतियां- एक समीक्षा

मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

1. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों को प्रशिक्षण और विस्तार सूविधाओं में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) की भूमिका
2. डीप सी फिशिंग का विकास

3. मत्स्य पालन क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादन के बाद का प्रबंधन- एक नजर
4. सी वीड की खेती का संवर्धन एवं विकास
5. फिशिंग हार्बर्स का विकास और आधुनिकीकरण
6. इन-लैंड फिशिंग फार्मों का विकास
7. पशुधन बीमा योजनाओं का मूल्यांकन
8. राष्ट्रीय पशुधन मिशन- एक मूल्यांकन
9. स्वदेशी मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की भूमिका
10. डेयरी क्षेत्र में पोषण और आजीविका की गुंजाइश - एक विश्लेषण
11. पशुधन के विकास के लिए नीतियां और परियोजनाएं- एक मूल्यांकन
12. डेयरी क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि-विभिन्न योजनाओं की समीक्षा
13. डेयरी उत्पादों में गुणवत्ता नियंत्रण का मूल्यांकन
14. गोजातीय पशुओं में प्रचलित बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के उपाय

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

1. "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में की गई पहल
2. भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की गुंजाइश
3. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास
4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना

सहकारिता मंत्रालय

1. देश में सहकारी समितियों के विकास के लिए नई योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्माण
2. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस की स्थापना में प्रगति
3. सहकारी चीनी मिलों (सीएसएम) के सुदृढीकरण में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की भूमिका
4. देश की सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक प्रथाओं का मूल्यांकन और प्रशासनिक हस्तक्षेप को कम करना
5. किसानों और मछुआरों की आय बढ़ाने में सहकारी समितियों की भूमिका- एक समीक्षा

रसायन एवं उर्वरक

1. उर्वरकों के आयात पर अंकुश लगाने के लिहाज से उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता- उनकी बाधाओं की समीक्षा
2. अचल संपत्तियों के रूप में नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स जो उर्वरक विभाग के तहत परिचालन में हैं और भविष्य का मार्ग- एक समीक्षा
3. उर्वरक सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से संबंधित मामले- एक समीक्षा
4. घरेलू उर्वरक उद्योग की वृद्धि सुनिश्चित करने की पहल

5. उर्वरक और कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक परियोजनाएं और संयुक्त उद्यम
6. उर्वरक उत्पादक सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन का मूल्यांकन
7. उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की विधि
8. आदेश के उल्लंघन के लिए दंड लगाने की प्रभावशीलता के विशेष संदर्भ में उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 के कार्यान्वयन का मूल्यांकन
9. उर्वरक सबसिडी योजनाओं के साथ-साथ उर्वरक नवाचार योजनाओं का मूल्यांकन और निगरानी
10. बीमार इकाइयों के पुनरुद्धार इत्यादि सहित कई उपायों द्वारा भारत को रसायनों और पेट्रोसायनों के अग्रणी निर्माता के रूप में स्थापित करना
11. केंद्रीय पेट्रोसायन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान (सीआईपीईटी) के कामकाज की समीक्षा
12. ड्राई-वस्तुओं और ड्राई इंटरमीडिएट्स उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक
13. कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) के कामकाज की समीक्षा
14. प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्रों की स्थापना और देश में प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम से कम करने के लिए उठाए गए कदम
15. मोलासेस, लिथियम और बैटरियों का उत्पादन- एक समीक्षा
16. पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)
17. फूडग्रेड प्लास्टिक की कंप्रोमाइज्ड/सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के उपयोग के कारण स्वास्थ्य जोखिम और भारतीय जलवायु की चरम स्थितियों में उनका संपर्क
18. फार्मास्युटिकल क्षेत्र में दवाओं की कीमत में वृद्धि का आम नागरिकों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव- एक समीक्षा
19. फार्मास्युटिकल क्षेत्र में रेगुलेटरी अर्थॉरिटीज़ की वर्तमान भूमिका और कार्यों का मूल्यांकन और कड़े सुधारों की आवश्यकता
20. कड़े गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानकों के साथ फार्मास्युटिकल उद्योग का समावेशी विकास, साथ ही स्वदेशी/पारंपरिक दवाओं और चिकित्सा पद्धतियों के उपयोग को बढ़ावा देना
21. उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से सक्रिय फार्मास्युटिकल वस्तुओं (एपीआई) के उत्पादन और उपलब्धता में आत्मनिर्भरता
22. राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) की स्थापना के बाद से उसकी गतिविधियों और प्रदर्शन की समीक्षा
23. नकली और मिलावटी दवाओं पर कड़े नियंत्रण के लिए रेगुलेटरी अर्थॉरिटीज़ के प्रदर्शन की समीक्षा

कोयला

1. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की संगठनात्मक संरचना और प्रदर्शन- एक समीक्षा
2. कोयला/लिग्नाइट खनन क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के मुद्दे
3. कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास
4. भारत के एनर्जी मिक्स में कोयले का भविष्य
5. देश में अवैध कोयला खनन और कोयले की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और सतर्कता गतिविधियों का कार्यान्वयन
6. कोयला/लिग्नाइट कंपनियों द्वारा पर्यावरण मानदंडों का अनुपालन
7. कोयला खदान श्रमिक कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा
8. कोयला खदानों में सुरक्षा
9. कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन- अनुमान और योजना
10. कोयला/लिग्नाइट क्षेत्र में कौशल विकास
11. कोयला नियंत्रक कार्यालय का प्रदर्शन
12. कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) का प्रदर्शन
13. कोयला वितरण और विपणन- एक समीक्षा

खनन मंत्रालय

1. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की संगठनात्मक संरचना और प्रदर्शन- एक समीक्षा
2. भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) की संगठनात्मक संरचना और प्रदर्शन- एक समीक्षा
3. देश में लौह अयस्क, मैंगनीज, जस्ता, चूना पत्थर, बॉक्साइट आदि के अवैध खनन पर अंकुश लगाने के उपाय
4. जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) फंड का कार्यान्वयन और उपयोग, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेवाई)- एक समीक्षा तथा अनुबंध श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और उनके लिए राहत और पुनर्वास
5. पूर्वोत्तर राज्यों में खनिज अन्वेषण गतिविधियां और क्षेत्र के विकास पर उनका समग्र प्रभाव
6. खनिज नीति एवं उसका क्रियान्वयन
7. खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण एवं वन मंजूरी प्रक्रिया को तेज और सरल बनाना
8. खनन गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के कारण प्रदूषण को कम करने के उपाय- चित्तौड़गढ़ किले सहित, एक केस स्टडी
9. खनिज और धातु क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
10. विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम और स्वायत्त निकाय

स्टील मंत्रालय

1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की संगठनात्मक संरचना और प्रदर्शन- एक समीक्षा
2. स्टील नीति की समीक्षा और आरएंडडी कौशल विकास आदि सहित स्टील क्षेत्र के विकास पर इसका प्रभाव
3. बंदरगाहों पर लौह अयस्क प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर

4. सेकेंडरी स्टील क्षेत्र की सहायता के लिए प्रमुख नीतिगत परिवर्तन
5. स्टील संयंत्रों द्वारा ऊर्जा दक्षता का प्रबंधन और लौह अयस्क खनन से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे
6. भारत में मैंगनीज अयस्क उद्योग का विकास
7. स्टील के उपयोग को बढ़ावा देना
8. स्टील पीएसयू की ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं की स्थिति

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

1. सभी प्रकार के मीडिया से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा
2. फेक न्यूज पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा
3. प्रसार भारती संगठन के कामकाज की समीक्षा
4. फिल्म उद्योग का अवलोकन
5. ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत और संबंधित मुद्दे
6. केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के कामकाज की समीक्षा

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत और संबंधित मुद्दों का प्रभाव
2. सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म और उनका रेगुलेशन
3. नए युग में सूचना प्रौद्योगिकी समझौतों का प्रभाव
4. नई प्रकार की करंसीज की शुरुआत और उसका प्रभाव
5. डिजिटल और साइबर अपराध- रेगुलेशन और निगरानी

संचार मंत्रालय

1. डाक विभाग में रियल एस्टेट प्रबंधन
2. डाक विभाग से संबंधित मुद्दे और डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की समीक्षा
3. भारत में दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित मुद्दे
4. दूरसंचार मैनेजमेंट क्वॉलिफिकेशन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
5. दूरसंचार क्षेत्र में सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) मानक और उपभोक्ता संरक्षण
6. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिवेशन फंड (यूएसओएफ) के तहत योजनाओं/परियोजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

1. खाद्यान्न भंडारण: मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य की रणनीति
2. खाद्यान्नों का परिवहन: रेलवे के माध्यम से आवाजाही को अनुकूलित करना
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण: तकनीकी डेटा बेस को मजबूत करना
4. एफसीआई गोदामों में खाद्यान्न की बर्बादी को रोकने के लिए नियंत्रण उपाय
5. खाद्य तेल उद्योग: एक समीक्षा

6. चीनी, गन्ना और अनाज से इथेनॉल और जैव ईंधन उत्पादन: संभावनाएं और चुनौतियां
7. बाजार के कदाचार से मुकाबला: सटीकता, गुणवत्ता और माप मानकों को सुनिश्चित करना
8. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के विशिष्ट संदर्भ में अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना
9. शिशु उत्पादों और अन्य खाद्य उत्पादों में शक्कर की मात्रा के विशिष्ट संदर्भ में पैकड वस्तुओं का रेगुलेशन
10. बैंकिंग क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना
11. गुणवत्ता और मानकों को बरकरार रखने में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की भूमिका
12. उत्पादों की टेस्टिंग और कैंलिब्रेशन में एनटीएच की भूमिका का विस्तार करना

रक्षा

1. सैनिक स्कूलों, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (आरआईएमसी) और राष्ट्रीय सैन्य स्कूलों की समीक्षा
2. रणनीतिक स्थानों और सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के कामकाज की समीक्षा
3. पूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए पुनर्वास नीतियों, स्वास्थ्य सुविधाओं और अवसरों की समीक्षा
4. रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) का आधुनिकीकरण
5. सशस्त्र बल कर्मियों के कल्याण सहित डीपीएसयू द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी (सीएसआर) पहल की समीक्षा
6. एक स्वतंत्र, पेशेवर और सामरिक बल के रूप में भारतीय वायुसेना की समीक्षा
7. देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय सेना की भूमिका
8. देश की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय नौसेना की भूमिका
9. देश में तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय तटरक्षक बल के कामकाज की समीक्षा
10. दुर्गम और दूर-दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की भूमिका
11. प्रमुख अनुसंधान पहलों सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों के माध्यम से स्वदेशी रक्षा उत्पादन का आकलन
12. साइबर, काइनेटिक और नॉन-काइनेटिक युद्ध और एंटी-ड्रोन क्षमताओं सहित हाइब्रिड युद्ध के संदर्भ में सशस्त्र बलों की तैयारी
13. सीमा सुरक्षा सहित वर्तमान अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनजर रक्षा बलों की रणनीतिक परिचालनगत तैयारियों की समीक्षा
14. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के विभिन्न कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के अपग्रेडेशन की स्थिति

15. रक्षा संपदा संगठन द्वारा रक्षा भूमि का समेकन और छावनी बोर्डों की कार्यप्रणाली
16. सशस्त्र बलों में निकटतम परिजन (एनओके) नीति का आकलन
17. कठिन इलाकों में सक्रिय रूप से तैनात सशस्त्र बल कर्मियों के लिए बचाव कार्यों और तैयारी का आकलन

शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा एवं खेल

शिक्षा मंत्रालय

1. पीएम पोषण पर विशेष बल देते हुए समग्र शिक्षा योजना की समीक्षा, जिसमें मिड डे मील में पोषण को बढ़ावा देने के प्रयास और सेवा वितरण में निजी पक्षों की संलग्नता शामिल हैं
2. देश के सरकारी स्कूलों में दाखिले में गिरावट के कारणों की समीक्षा, जिसमें स्कूलिंग की गुणवत्ता पर मौजूदा आंकड़ों का विश्लेषण शामिल है
3. केंद्रीय विद्यालयों (केवी) और जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) का अधिक स्थानों तक विस्तार करने की जरूरत और व्यावहारिकता की समीक्षा और ऐसे विस्तार के मानदंड
4. पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) की समीक्षा
5. विभिन्न राज्यों की स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन की समीक्षा
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर राज्य सरकारों की आपतियों की समीक्षा
7. निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार (आरटीआई) एक्ट, 2009 की समीक्षा और जरूरी सुधार, जिसमें अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं
8. प्रत्येक राज्य में शिक्षकों की भर्ती से संबंधित नीति की समीक्षा तथा एनईपी-2020 के मद्देनजर देश में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की मौजूदा रिक्तियां
9. शिक्षकों के क्षमता निर्माण पर एनईपी 2020 के विशेष बल देने के मद्देनजर शिक्षक प्रशिक्षण को सहयोग देने वाली राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) और अन्य कदमों की समीक्षा
10. केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों को दिए गए अनुदान की समीक्षा और स्कूलों द्वारा ऐसे अनुदानों का उपयोग
11. पाठ्यक्रम विकास और पाठ्यपुस्तकों की रचना के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के कामकाज की समीक्षा
12. स्कूली पाठ्यक्रम के अंग के रूप में कानून, नागरिक शास्त्र की शिक्षा, नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कृषि विज्ञान और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए किए गए मौजूदा प्रयासों की समीक्षा
13. स्कूल स्तर और स्कूलिंग में बोर्ड स्तर पर निरंतर मूल्यांकन को सहयोग देने के प्रयासों की समीक्षा
14. प्रत्येक राज्य में सरकारी प्रशासन द्वारा निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दिशानिर्देशों की समीक्षा

15. निजी स्कूलों द्वारा शुल्क संरचना के निर्माण के लिए राज्य सरकारों के दिशानिर्देशों की समीक्षा
16. अल्पसंख्यकों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की समीक्षा, जिसमें छात्रवृत्ति अनुदान और उन अनुदानों को उपलब्ध कराने वाले ऑनलाइन पोर्टल शामिल हैं
17. विकलांग बच्चों की शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए उठाए जाने वाले कदमों और योजनाओं की समीक्षा और स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर को समावेशी/विकलांग अनुकूल बनाने के लिए वित्त पोषण की स्थिति
18. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी), राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए), राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए), राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) इत्यादि के कामकाज की समीक्षा, एनईपी 2020 संबंधी पहलों पर विशेष ध्यान देते हुए
19. प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों की सहायता के लिए कोचिंग सेंट्रों के प्रसार, उससे उत्पन्न होने वाले सामाजिक मुद्दों और इस मामले पर मौजूदा कानून की समीक्षा
20. लोक सेवाओं में भ्रती तथा सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रश्न पत्रों में लोक की घटनाओं और उनके स्तर की समीक्षा, जिसमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) का कामकाज और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट, 2024 शामिल हैं
21. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) के कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण का समर्थन करने के अन्य उपाय
22. भारत में उच्च शिक्षा की वित्तीय पहुंच और शिक्षा ऋण की उपलब्धता की समीक्षा, तथा पहुंच बढ़ाने के लिए मौजूदा सरकारी योजनाएं
23. शैक्षणिक संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी फीस की समीक्षा
24. उच्च शिक्षा में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों के कामकाज की समीक्षा
25. सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र में क्वालिटी फेकेल्टी/टीचिंग रिसोर्सज की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले मुद्दे, और उच्च शिक्षा में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करना
26. उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण
27. उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को समर्थन देने के प्रयासों की समीक्षा

28. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन की प्रगति और शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर इसके प्रभाव की समीक्षा
29. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा)- प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रोडमैप
30. निजी विश्वविद्यालयों की मान्यता हेतु अपनाए गए दिशानिर्देशों की समीक्षा
31. मास्टर्स प्रोग्राम को एक साल की अवधि में स्थानांतरित करने की नीतियों की समीक्षा और उच्च शिक्षा पर उसका प्रभाव
32. राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से संबद्ध अनुसंधान सहयोगियों के लिए अनुदान के वितरण की समीक्षा

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

1. बेटे बचाओ, बेटे पढ़ाओ के क्रियान्वयन की समीक्षा
2. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना की समीक्षा, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन और कामकाजी परिस्थितियों पर ध्यान देना, मिड डे मील में पोषण को बढ़ावा देने के प्रयास और सेवा वितरण में निजी पक्षों की संलग्नता शामिल हैं
3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में एनीमिया और कुपोषण से निपटने की योजनाओं की समीक्षा
4. बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजनाओं की समीक्षा
5. बाल शोषण को रोकने और उसे दूर करने के प्रयासों की समीक्षा
6. विशेषकर अनौपचारिक नौकरियों में बाल श्रम कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा
7. मिशन शक्ति एवं मिशन वात्सल्य की समीक्षा
8. राष्ट्रीय महिला आयोग के कामकाज की समीक्षा और आयोग की शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार की गुंजाइश
9. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) एक्ट, 2013: अनौपचारिक नौकरियों सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कार्यान्वयन
10. भारत में गोद लेने की प्रक्रिया और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा) की कार्यप्रणाली की समीक्षा
11. महिलाओं और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी प्रयासों की समीक्षा
12. महिलाओं के लिए असमान वेतन और कम नौकरी के अवसरों की मौजूदगी और व्यापकता का मूल्यांकन
13. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की नौकरियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा
14. मीडिया में महिलाओं को रुढ़िबद्ध तरीके से प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति की समीक्षा
15. राष्ट्रीय युवा नीति, 2021 की समीक्षा: स्थिति और दृष्टिकोण
16. युवाओं में नशीली दवाओं और शराब के उपयोग की प्रवृत्ति की समीक्षा और प्रसार को रोकने के उपाय

17. राष्ट्रीय सेवा योजना एवं उसकी कार्यप्रणाली एवं वित्तपोषण की समीक्षा
18. नेहरू युवा केंद्र संगठन एवं उसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा
19. बेहतर अवसरों के लिए देश छोड़ने वाले युवाओं के प्रतिभा पलायन की व्यापकता और प्रभाव की समीक्षा
20. युवाओं के लिए प्रौद्योगिकी और इंटरनेट की सुविधा में सुधार के प्रयासों की समीक्षा
21. युवा एवं किशोर विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की समीक्षा
22. नौकरियों हेतु प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की समीक्षा
23. टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) की समीक्षा और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में शीर्ष प्रदर्शन के लिए चल रही तैयारी
24. भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के कामकाज और प्रदर्शन की समीक्षा
25. खेलो इंडिया योजना की प्रगति और जमीनी स्तर पर खेल को बढ़ावा देने, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और प्रतिभा की पहचान और पोषण पर प्रभाव की समीक्षा
26. खेलों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के तंत्र की समीक्षा
27. राष्ट्रीय खेल महासंघों के शासन और कामकाज की समीक्षा, और राष्ट्रीय खेल महासंघों और खेल विभाग के बीच संबंध
28. खेल संगठनों में प्रबंधन एवं जवाबदेही की समीक्षा
29. ग्रामीण एवं स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों की समीक्षा और ग्रामीण खेल विकास
30. कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) सहित खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के विकास में निवेश के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की समीक्षा
31. स्कूली शिक्षा के नियमित हिस्से के रूप में खेल को संलग्न करने के लिए मौजूदा तंत्र का मूल्यांकन
32. खेलों में प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के प्रयोग की घटनाओं को रोकने और कम करने के प्रयासों की समीक्षा

ऊर्जा

ऊर्जा मंत्रालय

1. भारत में ऊर्जा सुरक्षा- किफायती मूल्य पर ऊर्जा की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. ऊर्जा परिवर्तन- देश में ऊर्जा क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों पर प्रमुख जलवायु उपायों को अपनाने के प्रभाव।
3. ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता
4. थर्मल (कोयला और गैस आधारित) बिजली संयंत्रों का प्रदर्शन- पर्याप्त मात्रा में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना
5. देश में हाइड्रो पावर क्षेत्र का पुनरुद्धार

6. ट्रांसमिशन क्षेत्र का पुनरुद्धार- इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और बिजली प्रणाली में उच्च मांग का प्रबंधन
7. बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत बनाना- समय तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) घाटे और स्मार्ट मीटरिंग पर विशेष ध्यान देने के साथ पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना
8. विद्युत क्षेत्र में आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना
9. गो इलेक्ट्रिक- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की सुविधा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
10. विद्युत क्षेत्र की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना
11. भारत में विद्युत क्षेत्र के कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के लिए कार्य योजना
12. विद्युत क्षेत्र के विकास में विद्युत क्षेत्र के वैधानिक निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थानों की भूमिका
13. बिजली क्षेत्र में उभरता परिदृश्य और एक नई बिजली नीति की आवश्यकता- एक मूल्यांकन
14. पंप स्टोरेज संयंत्रों और बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणालियों के विकास के लिए कार्य योजना

नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय

1. 2030 तक नॉन-फॉसिल फ्यूएल आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता की उपलब्धि के लिए रोडमैप
2. देश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का प्रदर्शन मूल्यांकन
3. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)- एक मूल्यांकन
4. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना- ग्रिड से जुड़ी सोलर रूफटॉप पहल
5. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन- भारत के लिए ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने में हरित हाइड्रोजन की भूमिका
6. अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से चौबीसों घंटे बिजली (आरटीसी) सुनिश्चित करना
7. राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम- एक मूल्यांकन
8. हरित ऊर्जा कॉरिडोर- अक्षय ऊर्जा के लिए निकासी और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
9. अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता- उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना
10. अक्षय ऊर्जा वित्तपोषण- अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में त्वरित विकास की कुंजी के रूप में सुदृढ़ और नवोन्वेषी वित्तपोषण
11. अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में नई तकनीक- अपतटीय पवन, भू-तापीय और महासागरीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति
12. अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास
13. अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण

विदेशी मामले

1. एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई और प्रवासी श्रमिक सहित प्रवासी भारतीय: इमिग्रेशन बिल की स्थिति सहित उनकी स्थिति और कल्याण के सभी पहलू
2. भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य
3. भारत-श्रीलंका संबंध और भविष्य का मार्ग
4. लुकिंग वेस्ट: पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध
5. भारत की हिंद महासागर रणनीति का मूल्यांकन
6. भारत की लुक ईस्ट नीति: भारत-आसियान साझेदारी की समीक्षा
7. भारत-मालदीव भूराजनीति: चुनौतियां, अवसर और भविष्य का मार्ग
8. अफ्रीकी देशों में अवसर और भारत की भागीदारी
9. क्वाड की भूमिका
10. भारत यूरोप संबंध: अवसर और चुनौतियां
11. विदेशों में भारतीय मिशन का कामकाज: एक आकलन और मूल्यांकन
12. संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न निकायों में भारत की भूमिका और यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए उसका दावा
13. आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में भारत की भूमिका और उपस्थिति
14. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विदेशी आर्थिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाना
15. ई-पासपोर्ट सहित पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली का प्रदर्शन और भारतीय पासपोर्ट एक्ट और नियमों की समीक्षा
16. छोटे द्वीपीय देशों के साथ भारत की संलग्नता

आवासन एवं शहरी मामले

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
2. कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत)
3. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के कार्यान्वयन का मूल्यांकन
4. पीएम-ईबस सेवा योजना
5. मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों यानी स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्ट्रीट वैंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) आदि की प्रगति की समीक्षा
6. विभिन्न शहरों में मेट्रो की आवश्यकता एवं प्रगति की समीक्षा
7. रियल एस्टेट (रेगुलेशन और विकास) एक्ट, 2016 का कार्यान्वयन
8. क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और एनसीआरटीसी की भूमिका
9. स्लम्स का पुनर्विकास और पुनर्वास
10. शहरों में स्ट्रीट वैंडर्स के लिए वेंडिंग जोन की योजना, निर्धारण, निर्माण और विकास।

11. हुडको, एनबीसीसी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गनाइजेशन के कामकाज की समीक्षा
12. जनरल पूल रेसिडेंशियल आवास (जीपीआरए) कॉलोनियों का पुनर्विकास और सरकारी आवासीय क्वार्टरों के विस्तार के उपाय
13. शहरों में जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना
14. अर्बन प्लानिंग में पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी तकनीकें
15. शहरी स्थानीय निकायों/नगर निकायों के क्षमता निर्माण और वित्त पोषण के स्रोतों को बढ़ाना
16. विश्व धरोहर शहरों और धार्मिक महत्व के शहरों की विकासात्मक रणनीतियों का मूल्यांकन
17. दिल्ली और अन्य शहरों में अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण
18. दिल्ली और अन्य शहरों के मास्टर प्लान का कामकाज
19. एनसीआर में अपशिष्ट जल प्रबंधन, जल निकासी और सीवेज निपटान
20. दिल्ली में लैंड पूलिंग नीति के कार्यान्वयन की स्थिति
21. डीडीए द्वारा फ्लैटों की निर्माण और आवंटन नीति
22. हॉलिडे होम और टूरिंग ऑफिसर हॉस्टल के कामकाज की समीक्षा
23. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

श्रम, कपड़ा एवं दक्षता विकास

श्रम और रोजगार मंत्रालय

1. श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन
2. अनाधिकृत खदानों और खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के कामकाज के मूल्यांकन सहित खदान श्रमिकों के लिए काम करने की स्थिति और कल्याण उपाय
3. सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/प्रतिष्ठानों में कॉन्ट्रैक्ट/आकस्मिक श्रमिकों की कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियां/तैनातियां और उनके कल्याण से संबंधित श्रम कानूनों का कार्यान्वयन
4. बागान श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपायों का कार्यान्वयन
5. ईपीएफ पेंशन योजना के कार्यान्वयन और कॉर्पस फंड के प्रबंधन के विशेष संदर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कार्यप्रणाली
6. केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली
7. केंद्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन
8. बंधुआ मजदूरों की पहचान एवं पुनर्वास
9. विभिन्न रोजगार क्षेत्रों में निर्धारित न्यूनतम वेतन का कार्यान्वयन
10. गिग/स्कीम वर्कर्स, स्ट्रीट वैंडर्स, स्टोन क्रशर, मछुआरों और आईटी और दूरसंचार क्षेत्रों के श्रमिकों सहित असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपाय

11. विशेष रूप से पश्चिम एशिया क्षेत्र में ओवरसीज़ कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों और स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय
12. रोजगार सृजन कार्यक्रम- एक समीक्षा
13. महिला श्रमबल का सशक्तिकरण- उनकी कामकाजी परिस्थितियों और उनके लिए उपलब्ध विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की अंतर्दृष्टि
14. भारत और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)- उद्देश्यों की प्राप्ति और भारत पर बाध्यकारी कन्वेंशंस की समीक्षा
15. ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों- चुनौतियों और समाधान के विशेष संदर्भ में ईएसआईसी के माध्यम से संगठित और असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों और उनके परिवारों को किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का विस्तार और प्रदान करना
16. रेलवे, रोडवेज, एयरलाइंस और बंदरगाहों में श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय

कपड़ा मंत्रालय

1. कपड़ा क्षेत्र में मैन्यूफैक्चरिंग और अपग्रेडेशन के साथ-साथ कौशल विकास
2. भारतीय कपड़ा उद्योग की चुनौतियां/अवसर
3. हथकरघा क्षेत्र की स्थिति/प्रदर्शन
4. पावरलूम क्षेत्र की स्थिति एवं सुधार
5. हथकरघा और हस्तशिल्प की मार्केटिंग एजेंसियों का प्रदर्शन
6. राष्ट्रीय कपड़ा निगम (एनटीसी) की कार्यप्रणाली
7. ऊन क्षेत्र की चुनौतियां/अवसर
8. कपड़ा क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भागीदारी का दायरा
9. टेक्सटाइल क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम (टीसीडीएस) के कामकाज की समीक्षा
10. कपड़ा उत्पादन से निकलने वाले कचरे का पर्यावरण पर प्रभाव और इसे रोकने के लिए किए गए उपाय/पहल
11. कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ-योजना के कामकाज की समीक्षा
12. रेशम उत्पादन पर विशेष ध्यान देने के साथ पूर्वोत्तर वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) के तहत चुनौतियां और संभावनाएं
13. पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देने तथा विलुप्त होती कलाओं के संरक्षण के उपाय
14. प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) योजना का कार्यान्वयन

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

1. राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा- एक आकलन
2. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की कार्यप्रणाली
3. खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण
4. अग्निवीरों के कौशल की पहचान योजना- एक आकलन

5. नई आईटीआई उन्नयन योजना की शुरुआत
6. एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत कौशल विकास
7. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की कार्यप्रणाली

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

1. पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण, मार्केटिंग और आपूर्ति
2. तेल सार्वजनिक उपक्रमों की खरीद प्रक्रियाओं में अनुबंध प्रबंधन और पारदर्शिता
3. बीपीसीएल रिफाइनरीज के प्रदर्शन की समीक्षा
4. तेल सार्वजनिक उपक्रमों की मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा
5. तेल पीएसयू की सीएसआर गतिविधियां
6. 'आत्मनिर्भर भारत योजना' के तहत तेल पीएसयू की पहल
7. कच्चे तेल की आयात निर्भरता कम करने के लिए उठाए गए कदम
8. सीजीडी परियोजनाओं सहित तेल पीएसयू की परियोजनाओं की समीक्षा
9. तेल सार्वजनिक उपक्रमों की खोज और उत्पादन गतिविधियों की समीक्षा
10. तेल पीएसयू की आरएंडडी गतिविधियों की जांच
11. नेट-जीरो की स्थिति हासिल करने की दिशा में तेल पीएसयू की पहल
12. पेट्रोलियम क्षेत्र में सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी मुद्दे
13. कोल बेड मीथेन नीति की समीक्षा
14. पूर्वोत्तर के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030 को लागू करने की दिशा में इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड की समीक्षा
15. भारत में बीएस VI अनुरूप ईंधन के उत्पादन और खपत पैटर्न की समीक्षा
16. देश में एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा
17. तेल पीएसयू के अंतरराष्ट्रीय कामकाज और निवेश की जांच
18. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन-तेल सार्वजनिक उपक्रमों के लिए अवसर और चुनौतियां
19. एसएटीएटी और बायो-डीजल योजनाओं की समीक्षा

रेलवे

1. भारतीय रेल के कामकाज में सुरक्षा सुनिश्चित करना
2. रेलवे भूमि का अधिकतम उपयोग
3. भारतीय रेलवे की विभिन्न विस्तार और उन्नयन संबंधी परियोजनाओं की स्थिति और उनका वित्तपोषण
4. भारतीय रेलवे के विकास और विस्तार में रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका
5. रेलवे स्टेशनों पर जनसुविधाओं में सुधार
6. रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज सहित रेल सुरंगों और पुलों का निर्माण और रखरखाव
7. भारतीय रेलवे में मानव संसाधन प्रबंधन

8. भारतीय रेलवे में पटरियों और सिग्नलिंग का उन्नयन
9. भारतीय रेलवे की माल ढुलाई संबंधी आय में वृद्धि और समर्पित माल गलियारों का विकास
10. भारतीय रेलवे की उपनगरीय ट्रेन सेवा
11. भारतीय रेलवे में यात्री आरक्षण प्रणाली
12. भारतीय रेलवे में ऊर्जा दक्षता
13. भारतीय रेलवे में ऑनबोर्ड सेवाओं का मूल्यांकन
14. पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेशों में रेल नेटवर्क का विस्तार
15. तटीय क्षेत्रों में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और परियोजनाओं की समीक्षा
16. भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयों और रेलवे वर्कशॉप्स का प्रदर्शन
17. रेलवे आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना
18. भारत में हाई स्पीड रेल नेटवर्क
19. मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के विकास और सड़क एवं बंदरगाह नेटवर्क के साथ उनके एकीकरण में भारतीय रेलवे की भूमिका
20. स्वदेशी स्रोतों के नवाचार और प्रचार के माध्यम से भारतीय रेलवे को आत्मनिर्भर बनाना

सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम (एनएसएफडीसी) के कामकाज की समीक्षा
2. एससी, ओबीसी और खतरनाक एवं अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं जिसमें मूल्यांकन अध्ययन और उनका कार्यान्वयन शामिल
3. एससी, ओबीसी, डीएनटी और ईबीसी के लिए कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण
4. सामाजिक कल्याण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को सहायता अन्दान और उनके कामकाज और प्रदर्शन का मूल्यांकन
5. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) के कामकाज की समीक्षा
6. ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट के कामकाज की समीक्षा
7. दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) की कार्यप्रणाली की समीक्षा
8. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन
9. सुगम्य भारत अभियान की समीक्षा
10. आदिवासियों के शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं
11. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के कामकाज की समीक्षा
12. आदिवासी उत्पादों के लिए मार्केटिंग सहायता की समीक्षा
13. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के कामकाज की समीक्षा

14. ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड) के कामकाज की समीक्षा
15. कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत आदिवासियों के कल्याण के लिए लागू योजनाएं/कार्यक्रम
16. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी एक्ट, 2006 के कार्यान्वयन की समीक्षा
17. अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा
18. कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यान्वित योजनाएं/कार्यक्रम
19. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेकेवाई) के कार्यान्वयन की समीक्षा
20. प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) की समीक्षा
21. एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी के कल्याण के लिए एनजीओ/सोसाइटीज को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की समीक्षा
22. बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति

1. ई-मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति और ई-वाहनों की वृद्धि की समीक्षा
2. राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात की भीड़ और अतिक्रमण को दूर करना
3. राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से संबंधित मुद्दे;
4. उड़ान योजना और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड के कार्यान्वयन की समीक्षा
5. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के कामकाज की समीक्षा
6. सांस्कृतिक मानचित्रण और रोडमैप पर राष्ट्रीय मिशन तथा स्थानीय और स्वदेशी कला का संवर्धन
7. प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों का डिजिटल संरक्षण और कलाकृतियों का दस्तावेज़ीकरण
8. समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार
9. बंदरगाहों का विकास: चुनौतियां और समाधान
10. आध्यात्मिक पर्यटन पर विशेष जोर देते हुए थीम आधारित पर्यटक सर्किट का विकास

जल संसाधन

1. नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में संरक्षण, विकास, प्रबंधन और प्रदूषण में कमी, विशेष रूप से परियोजना वितरण और समय सीमा के साथ-साथ राज्य सरकारों के प्रदर्शन के संदर्भ में
2. कावेरी नदी और दक्षिण भारत की अन्य प्रमुख नदियों का संरक्षण और प्रदूषण का उन्मूलन
3. देश में अटल भूजल योजना और भूजल प्रबंधन का कार्यान्वयन

4. देश में बाढ़ का परिदृश्य और अत्यधिक बाढ़ से निपटने के लिए किए गए उपायों की प्रभावशीलता
5. बांधों की सुरक्षा के उपाय
6. पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता में सुधार के लिए नदियों को आपस में जोड़ना
7. भारत में जल उपयोग दक्षता
8. बाढ़ और मिट्टी के कटाव की समस्या के विशेष संदर्भ में पूर्वोत्तर राज्यों में जल संसाधन प्रबंधन
9. जल निकायों का रखरखाव और निर्माण- (i) सरकार और स्थानीय निकायों की भूमिका; और (ii) कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत उद्योग
10. भारत में वर्षा जल संचयन
11. नदी तटों, बाढ़ के मैदानों की सुरक्षा और मिट्टी के कटाव के नियंत्रण के लिए पहल
12. सिंचाई के लिए पानी की कमी की समस्या के विशेष संदर्भ में जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव
13. डब्ल्यूपीसीओसी लिमिटेड और एनपीसीसी लिमिटेड की भूमिका और कार्यप्रणाली की समीक्षा
14. सतत विकास के लिए समावेशी जल योजना
15. तटीय क्षेत्रों में बाढ़ से उत्पन्न खतरे को कम करने में उन्नत प्रौद्योगिकियों की भूमिका
16. जल स्रोतों का संदूषण; जल प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार कारक और उपचारात्मक उपाय
17. वन क्षेत्रों, टाइगर रिजर्व्स और सैंचुरीज़ में जल प्रबंधन
18. नदी तटबंध/नदी तट और आर्द्रभूमि में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण

19. देश में बैकवाटर प्रबंधन, ठहराव और कमी
20. पूर्वोत्तर जल प्रबंधन अथॉरिटी के कामकाज की समीक्षा-अथॉरिटी के तहत अधिदेश, कार्य योजना और परियोजना गतिविधियों की समीक्षा
21. भारत में प्रमुख, मध्यम और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति और प्रगति के साथ समीक्षा (i) सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम); (ii) जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए); और (iii) ड्रिप सिंचाई/स्प्रिंकलर
22. तटीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति- अलवणीकरण संयंत्रों की स्थापना
23. ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता- मुद्दे और दृष्टिकोण
24. ग्रामीण भारत में पेयजल की गुणवत्ता- मुख्य कदमों और उपलब्धियों की समीक्षा
25. ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्रोतों का संरक्षण, विकास, प्रबंधन और प्रदूषकों/संदूषण का उन्मूलन
26. जल जीवन मिशन के प्रदर्शन की समीक्षा- ग्रामीण क्षेत्र में जेजेएम के तहत पाइपड जलापूर्ति इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता और कार्यात्मक स्थिरता
27. स्वच्छ भारत मिशन-चरण II के प्रदर्शन की समीक्षा - (i) सभी गांवों के लिए ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) प्लस लक्ष्य की उपलब्धि के विशेष संदर्भ में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए स्वच्छता इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता और स्थिरता और (ii) गोबरधन, देश में अपशिष्ट से संपत्ति निर्माण की पहल

¹ Consumer Price Index Numbers on Base 2012=100 for Rural, Urban and Combined for the Month of September 2024, National Statistics Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, October 14, 2024, https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/CPI_PR_14oct24.pdf.

² "Index Numbers of Wholesale Price in India for the Month of September, 2024 (Base Year: 2011-12)", Press Information Bureau, Ministry of Commerce and Industry, October 14, 2024, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2064586>.

³ Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) October 7 to 9, 2024, Monetary Policy Statement, 2024-25, Reserve Bank of India, October 9, 2024, <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR1252500AD1D6DF27491B900F3C41B7FAE460.PDF>.

⁴ F. NO-CSR/13/35/2024, Ministry of Corporate Affairs, October 3, 2024, https://pminternship.mca.gov.in/assets/docs/PMIS_Guidelines.pdf.

⁵ Writ Petition (Civil) No. 274 of 2009, Supreme Court of India, October 17, 2024, https://api.sci.gov.in/supremecourt/2009/16113/16113_2009_1_1501_56604_Judgement_17-Oct-2024.pdf.

⁶ Citizenship Act, 1955, <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1522/1/a1955-57.pdf>.

⁷ Article 14, Part 3, Constitution of India, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15240/1/constitution_of_india.pdf.

⁸ Civil Appeal No. 152 of 2007, State of U.P. vs M/S. Lalta Prasad Vaish and Sons, Supreme Court of India, October 23, 2024, https://api.sci.gov.in/supremecourt/2005/12996/12996_2005_1_1501_56796_Judgement_23-Oct-2024.pdf.

⁹ Entry No. 8, List II, Seventh Schedule, The Constitution of India.

¹⁰ "Cabinet approves the PM Rashtriya Krishi Vikas Yojana (PM-RKVY) to promote sustainable agriculture and Krishonnati Yojana (KY) to achieve food security for self sufficiency", Press Information Bureau, Cabinet, October 3, 2024, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2061649>.

¹¹ "Cabinet Approves National Mission on Edible Oils – Oilseeds (NMEO-Oilseeds) for 2024-25 to 2030-31", Press Information Bureau, Cabinet, October 3, 2024, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2061646>.

¹² Third Advance Estimates of production of Foodgrains, Oilseeds and Other Commercial Crops for the year 2023-24 – released on June 4, 2024, https://dfpd.gov.in/Home/ContentManagement?Url=edible_oil_scenariorio.html&Manuld=3&language=1.

¹³ "Cabinet approves Minimum Support Prices (MSP) for Rabi Crops for Marketing Season 2025-26", Press Information Bureau, Cabinet Committee on Economic Affairs, October 16, 2024, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2065309>.

¹⁴ National Food Security Act, 2013, <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/21113/1/201320.pdf>.

¹⁵ "Cabinet approves continuation of supply of free Fortified Rice under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) and other welfare schemes from July, 2024 to December, 2028", Press Information Bureau, Cabinet, October 9, 2024, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2063446>.

¹⁶ Draft National Sports Governance Bill, 2024, <https://yas.nic.in/sites/default/files/Draft%20National%20Sports%20Governance%20Bill%20-2024.pdf>.

¹⁷ "Union Health Minister Unveils Key Initiatives to boost Nutrition Support for TB Patients and their Families", Ministry of Health and Family Welfare, Press Information Bureau, October 7, 2024, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2062928>.

¹⁸ Union Cabinet approves establishment of Rs.1,000 crore Venture Capital Fund for Space Sector under aegis of IN-SPACe, Department of Space, Press Information Bureau, October 24, 2024, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2067667>

¹⁹ Liquid Waste Management Rules, 2024, Ministry of Environment, Forest, and Climate Change, October 7, 2024, <https://egazette.gov.in/WriteReadData/2024/257748.pdf>.

²⁰ Environment (Protection) Act, 1986, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4316/1/ep_act_19_86.pdf.

²¹ National Electricity Plan (Volume 2) Transmission, Central Electricity Authority, https://cea.nic.in/wp-content/uploads/notification/2024/10/National_Electricity_Plan_Volume_II_Transmission.pdf.

²² National Electricity Plan (Volume 1) Generation, Central Electricity Authority, May 31, 2023, https://cea.nic.in/wpcontent/uploads/irp/2023/05/NEP_2022_32_FINAL_GAZETTE1.pdf.

²³ The Electricity Act, 2003, https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2058?sam_handle=123456789/1362.

²⁴ “MNRE notifies Scheme Guidelines for ₹500 crore ‘Innovative Projects’ component under PM-Surya Ghar Yojana”, Press Information Bureau, Ministry of New and Renewable Energy, October 11, 2024, <https://pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2064203®=3&lang=1>.

²⁵ “No.: 318/17/2024- Grid Connected Rooftop(part 14) Mission Directorate, PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana”, Press Information Bureau, Ministry of New and Renewable Energy, October 8, 2024, <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/oct/doc20241011414801.pdf>.

स्वीकरण: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।